साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 20-26 मार्च, 2023, वर्ष-8, अंक-49

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

-विदिशा-बीना में देखी बर्बाद फसल, ओलावृष्टि से प्रभावित मिले सीएम, बोले

» शिवराज ने कहा- किसी किसान की आंखों में नहीं आने दूंगा आंसू

» मप्र में बेटी की शादी के लिए 56 हजार रुपए देगी सराकर

किसानों से कर्ज वसूली स्थगित बिना ब्याज पर मिलेगा लोन

» 50 फीसदी फसल क्षति पर 32,000 रुपए हेक्टेयर राहत

» फसल बीमा योजना का क्लेम अलग से दिलवाया जाएगा

» पीएम से फोन पर चर्चा कर ओलावृष्टि से हुए क्षति की जानकारी दी

» प्रदेश में ईमानदारी और उदारतापूर्वक हर खेत का सर्वे किया जाएगा

» गेहूं, सरसों, धनिया, चना, मसूर सहित सभी फसलों का सर्वे होगा

» राजस्व, पंचायत और कृषि विभाग के कर्मचारी मिलकर सर्वे करेंगे

» सर्वे के बाद प्रभावितों की सूची पंचायत भवन में चस्पा की जाएगी

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों का जायजा लेने विदिशा और सागर जिले के बीना तहसील के ग्राम रूसल्ला ग्राम पहुंचकर ओलावृष्टि के कारण किसानों की क्षतिग्रस्त फसलों का खेत पर जाकर जायजा लिया। विदिशा के पटवारी खेड़ी गांव में सीएम शिवराज किसान के साथ खेत में बैठ गए। गेहूं की बालियों को देखा और बोले- चिंता मत करो मैं हूं। सर्वे कराया जा रहा है। जो भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाएगी। इससे पहले सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फसलों के नुकसान की जानकारी फोन पर दी। विदिशा के किसानों ने बताया कि 70 प्रतिशत तक नुकसान हो गया है। गेहूं के खेत में ओले गिरने से गेहूं की बालियां टूट कर गिर गई हैं। चने की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। सीएम शिवराज ने कहा कि हर खेत में मैं पहुंच नहीं सकता, लेकिन संदेश पूरे प्रदेश के किसानों के लिए है कि अगर फसलों को 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो 32 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से हम राहत राशि देंगे। हमने ये फैसला भी किया है कि प्रभावित किसानों से कर्ज वसूली स्थगित कर दी जाएगी।

पीएम को बताई फसलों का हाल

सरकार ने बर्बाद फसलों का सर्वे भी शुरू करा दिया है। 27 जिलों में प्रारंभिक नुकसान सामने आया है। सीएम ने 25 मार्च तक सर्वे पूरा करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बेमौसम बारिश और ओलों से फसल तबाह होने की जानकारी दी है। सीएम ने पीएम मोदी से फोन पर बात की।

भेड़-बकरी की मौत पर 4 हजार

पशु हानि, मकानों की क्षति पर भी राहत दी जाएगी। ओलावृष्टि या बिजली गिरने से मृत व्यक्ति के परिजनों को 4 लाख की सहायता दी जाएगी। गाय-भैंस की मौत होने पर 37 हजार रुपए, भेड़-बकरी की हानि होने पर 4 हजार देंगे। बछड़ा-बछिया पर 20 हजार और मुर्गा-मुर्गी की हानि होने पर प्रति मुर्गा-मुर्गी 100 रुपए दिए जाएंगे।

दोनों तरह की राहत राशि दी जाएगी

सागर जिले के खुरई, नरयावली, बीना में भी नुकसान पहुंचा है। किसानों को जो मुआवजा राशि दी जाएगी, वह तीन विभागों के संयुक्त दल द्वारा सर्वे करने के उपरांत दी जाएगी। जो विभाग संयुक्त दल में शामिल होंगे, उनमें कृषि, राजस्व और पंचायत विभाग शामिल रहेंगे। राहत की राशि जो किसी राज्य में नहीं मिलती वह सरकार देगी।

मप्र के 3800 गांव में फसल बर्बाद

पहले फेज में 6 से 9 मार्च के बीच आंधी, पानी और ओले गिरने से 16 जिलों के 3280 गांव में 1.09 लाख किसान की 1.25 लाख हेक्टेयर की फसल नष्ट होने की जानकारी सामने आई है। रही सही कसर 16 मार्च के बीच बिगड़े मौसम ने पूरी कर दी। शुरुआती सर्वे में 27 जिलों में नुकसान माना जा रहा है। दूसरे फेज में अभी तक की रिपोर्ट में 19 जिलों के 525 गांवों में 33884 किसानों की 38985 हेक्टयर फसल खराब हो गई। दोनों फेज की प्रारंभिक सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो मप्र के साढ़े तीन हजार गांवों में 1.5 लाख हेक्टेयर की फसल को नुकसान हुआ है। वहां फसलों को 50 से 85 फीसदी तक नुकसान माना जा रहा है।

सीएम बोले-उपार्जन कार्य की जरूरी तैयारियां पूरी करें

प्रदेश में 25 से शुरू होगी समर्थन पर गेहूं की खरीदी

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में रबी उपार्जन कार्य के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को पूर्ण करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में प्रदेश में रबी उपार्जन कार्य के लिए की गई तैयारियों संबंधी बैठक में यह निर्देश दिए। बताया गया कि प्रदेश में इस वर्ष उपार्जन के लिये करीब 15 लाख किसान पंजीयन करवा चुके हैं। 20 लाख पंजीयन की संभावना है। अनाज के भंडारण एवं परिवहन के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश में 25 मार्च से गेहूं उपार्जन शुरू होगा।

मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश

» भंडारण क्षमता अच्छी रखें।
» उपार्जन केंद्र पर्याप्त हों।
» बारदाने की कहीं भी कमी न हो।
» किसान को समय पर राशि का भुगतान हो।
» आवश्यक परिवहन व्यवस्था हो।
» उपार्जन से जुड़े कार्यों में तकनीक का उपयोग हो।
» किसान को उपार्जन के लिए खुद केंद्र के चयन की सुविधा दी जाए।
» न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को समय पर राशि का भुगतान किया जाए।

-11 महीने बाद अच्छी नस्ल की गायों के बछड़ों का होगा जन्म

मप्र के सागर में होगा टेस्ट ट्यूब एनिमल बेबी

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश में पहली बार सागर में टेस्ट ट्यूब एनिमल बेबी होगा। अभी तक भोपाल, अहमदाबाद, रुड़की की लैब में इसके परीक्षण हो रहे थे, जो सफल होने के बाद देश में मैदानी तौर पर मध्यप्रदेश के 10 जिलों का चयन किया है, जहां 2 महीने बाद अहमदाबाद-रुड़की की टीम आकर भ्रूण प्रत्यारोपण करेगी।

यानी 11 महीने बाद अच्छी नस्ल की गायों के बछड़े पैदा होंगे। आईवीएफ (इनविटरो फर्टीलिटी) तकनीक से गायों में प्रजनन का प्रयोग देश में अलग-अलग स्थानों पर पहले से चल रहा है, लेकिन इसे जमीन पर उतारने का काम अब शुरू किया जा रहा है। सागर जिले को इस तकनीक से प्रजनन के लिए 375 भ्रूण प्रत्यारोपण का लक्ष्य मिला है। इसके लिए गायों का चयन शुरू हो गया है।

बैल करेंगे तैयार | तकनीक का उपयोग करके देसी नस्ल की गाय और बैल तैयार करना है। अभी तक यह प्रयोग गिर और साहीवाल नस्ल की गायों पर किया जा रहा है। उपसंचालक वीके पटेल ने बताया यह प्रयोग राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत किया जा रहा है। काम शुरू हो गया है।

19500 रु. का अनुदान | नई तकनीक पर खर्च 21000 रुपए आ रहा है। शुरुआत में किसान को गायों का गर्भाधान कराने पर 19500 रुपए का अनुदान मिलेगा। यानी लोगों को प्रत्येक गर्भाधान पर 1500 देने होंगे। योजना में सागर, खंडवा, सीहोर, विदिशा, रायसेन, दमोह, छिंदवाड़ा, खरगोन, नरसिंहपुर, मुरैना जिला शामिल हैं।

नस्ल के मुताबिक दूध देगी गाय | टेस्ट ट्यूब एनिमल से बनी गाय अपनी नस्ल के मुताबिक दूध देगी। यानी गिर नस्ल का टेस्ट ट्यूब एनिमल बेबी तैयार किया तो वह 12-15 लीटर दूध रोज देगी। साहीवाल नस्ल की गाय तैयार की तो यह 12 से 20 लीटर तक दूध देगी।

ऐसे तैयार होंगे बेबी

गाय के अंडाणु और सांड के वीर्य का निषेचन टेस्ट ट्यूब में किया जाता है। इसमें सोनोग्राफी मशीन और ओवम पिकअप एसेबली की सहायता से गाय के अंडाणु को टेस्ट ट्यूब में एकत्रित किया जाता है। उसके गाय की ओवरी के तापमान में लैब में रखा जाता है। उसके बाद बेहतर नस्ल के वीर्य को अंडाणु से निषेचित कराया जाता है। इससे लैब के इंक्यूबेटर में इन्हें उचित तापमान में रखा जाता है। जिसके बाद टेस्ट ट्यूब एनिमल यानी एंब्रियो बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस तरह तैयार भ्रूण को कम उत्पादन क्षमता वाली गायों में प्रत्यारोपित किया जाएगा, ताकि उनकी नस्ल सुधार हो, दूध उत्पादन क्षमता बढ़े।

किस्मों की बुवाई से किसानों को 3-4 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज प्राप्त होती है

किसान अप्रैल महीने में करें इन 5 फसलों की खेती

भोपाल।

अप्रैल महीना जायद का सीजन होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती की जाती है। बसंत ऋतु में जब किसान अगेती फसल की कटाई का काम पूरा कर लेते हैं, तो खरीफ की बोवनी से पहले मूंग, मूंगफली, मक्का, अरहर, कपास, लोभिया आदि की खेती कर सकते हैं। क्योंकि इन फसलों को तैयार होने में बहुत ही कम समय लगता है।

मूंग और उड़द की खेती- किसान भाई अप्रैल महीने के दौरान अपने खाली पड़े खेत में मूंग की 338 किस्म व उड़द (मास) की टी 9 किस्म की खेती कर सकते हैं। बता दें कि मूंग की बुवाई के 67 दिनों बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है, वहीं मास 90 दिनों में पक जाते हैं। खास बात यह कि इन किस्मों की बुवाई से किसानों को 3-4 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज प्राप्त हो जाती है।

मूंगफली की खेती

मूंगफली की एम722 और एसजी 84 किस्मों की अप्रैल के अंतिम सप्ताह में बुवाई करनी चाहिए. यदि आप गेहूं की कटाई के तुरंत बाद मूंगफली की इन किस्मों की बुवाई करने से किसानों को अगस्त के अंत तक मूंगफली की अच्छी उपज प्राप्त हो सकती है। इसके बाद किसान उस खेत में धान की पछेती किस्म की बुवाई कर सकते हैं।

साठी मक्का और बेबी कार्न| साठी मक्का की पंजाब साठी-1 किस्म गर्मी के प्रति सहनशील है। साथ ही यह किस्म 70 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसके साथ ही मीठा भुट्टा या स्वीट कॉर्न की कम्पोजिट केसरी और संकर प्रकाश किस्म अप्रैल महीने में बोने के लिए उपयुक्त है। बुवाई के महज 60 दिनों में इसकी फसल पककर तैयार हो जाती है।

गन्ने की बुवाई

किसान भाई अप्रैल महीने के दौरान गन्ने की सीओएच -37 किस्म काफी उपयोगी है। किसानों को इस गन्ने की बुवाई दवि-पंक्ति विधि से करनी चाहिए।

चौलाई की खेती

चौलाई की खेती के लिए अप्रैल महीना बेहतरीन साबित हो सकता है। किसानों को चौलाई की पूसा किरण और पूसा कीर्ति की बुवाई करनी चाहिए। महज कुछ ही महीनों में किसानों को इससे अच्छा उत्पादन मिल सकता है।

मंडियों में सब्जियों के दाम हो जाते हैं महंगे

किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है करेले की खेती

डॉ. रजनी सिंह सासोड़े,
अनुप्रिया, प्रहलाद, प्रथम कुमार
सिंह, डॉ. प्रद्युम्न सिंह
राजमाता विजयाराजे सिंधिया
कृषि विवि, ग्वालियर

ग्वालियर। जागत गांव हमार

किसान अधिक मुनाफा पाने के लिए अपने खेत में सीजन के अनुसार फसल को उगाते हैं, ज्यादातर यह देखा गया है कि गर्मियों के मौसम में बाजार में सब्जियों की मांग काफी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मियों का सीजन ऐसा होता है कि इसमें सब्जियों की आवक बेहद कम हो जाती है, जिसका असर बाजार में देखने को मिलता है।

मंडियों में सब्जियों के दाम काफी अधिक हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में किसान अपने खेत में सब्जियों की खेती कर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए वह अपने खेत में भिंडी, तोरई, घीया, टिंडा, खीरा, ककड़ी और करेले की खेती कर सकते हैं किसान भाइयों के लिए करेले की खेती सबसे लाभदायक खेती में से एक है, क्योंकि इसकी खेती को एक साल में दो बार आसानी से किया जा सकता है।

करेले की सब्जी पर एक नजर: करेला अपने कड़वेपन और कुदरती गुणों के कारण बाजार में जाना जाता है। बता दें कि यह सब्जी स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद सब्जियों में से एक है। भारत में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है जैसे कि- कारवेल्लक कारवेल्लिका करेल करेली तथा करेला आदि लेकिन इनमें से करेला नाम सबसे अधिक लोकप्रिय है।

जाल विधि का करें इस्तेमाल

करेले की खेती के लिए जाल विधि सबसे उत्तम मानी जाती है, क्योंकि इसकी विधि से करेले की फसल से अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। किसान इस विधि में अपने पूरे खेत में जाल बनाकर करेले की बेल को फैला देता है। इस विधि से फसल पशुओं के द्वारा नष्ट नहीं होती है और साथ ही बेल वाली सब्जी होने के कारण यह जाल में अच्छे से फैल जाती है। इस विधि की सबसे अच्छी खासियत यह है कि किसान इसे नीचे क्यारियों की खाली जगह पर धनिया और मैथी जैसी अतिरिक्त सब्जियों को उगा सकते हैं।

ग्रीनहाउस और पॉली हाउस विधि

इन दोनों विधि के द्वारा किसान किसी भी समय अपने खेत में करेले की खेती से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखा जाए तो आज के समय में ऐसी नई किस्में भी बाजार में मौजूद हैं। जिससे किसान सर्दी गर्मी और बारिश तीनों ही मौसम में उगा सकते हैं।

प्रमुख किस्में

फैजाबाद स्माल, सुपर कटाई
सफेद लांग
ऑल सीजन
जोनपुरी
झालारी
हिरकारी
भाग्य सुरूचि
मेघा-एफ 1
वरून-1 पूनम
तीजारावी
अमन नं.- 24
नन्हा क्र.- 13
पूसा संकर 1
पीवीआईजी 1
आरएचबीबीजी 4
केबीजी16
फैजाबादी बारह मासी
अर्का हरित
पूसा 2 मौसमी
कोयम्बटूर लौंग
सी 16
पूसा विशेष
कल्याणपुर बारह मासी
हिसार सेलेक्शन

खेती के लिए उचित विधि

करेले की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए किसानों को इसकी खेती बलुई दोमट मिट्टी में करनी चाहिए। इसके साथ ही अच्छे जल निकास वाली भूमि को चुनें। इस बात का भी ध्यान रखें कि खेत में जलभराव वाली स्थिति ना बने। ऐसा करने से करेले की खेती को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। करेले की खेती में बीज बुवाई का भी ध्यान रखें। इसके लिए खेत में बीजों को 2 से 3 इंच गहराई पर ही बुवाई करें और नालियों की दूरी लगभग 2 मीटर व पौधों की दूरी 70 सेंटीमीटर रखें।

करेले की खेती में लागत व मुनाफा

अगर आप अपने खेत के 1 एकड़ में करेले की खेती करना शुरू करते हैं तो आपको करीबन 30 हजार रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे। खेत में ऊपर बताई गई तकनीकों का इस्तेमाल करें तो आप प्रति एकड़ लगभग 3 लाख रुपए तक का मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, आप अपनी लागत से 10 गुना अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं।

आत्मनिर्भर हो रहे किसान

देशभर की मंडियों में बढ़ी बड़वानी के अदरख की डिमांड

बड़वानी। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में अदरक का बंपर उत्पादन हो रहा हैं। जिले का अदरक देशभर की सभी मंडियों में सप्लाई जा रहा हैं । अदरक की खेती से बड़वानी के किसान समृद्ध हो रहे हैं और यह किसानों के लिए वरदान साबित हो ही है।

औषधी के रूप में प्रयोग होने वाले अदरक ने बड़वानी जिले के किसानों की आमदनी में बढ़ोत्तरी कर दी हैं। बड़वानी के अदरक ने जिले को एक अलग पहचान दिलाई हैं। इसने न सिर्फ प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में भी अपनी पहचान बना ली हैं। एक जिला, एक उत्पाद के तहत बड़वानी जिले की अदरक की फसल को चयनित किया गया है। यह अदरक की फसल को खास तरह की प्रोसीसिंग और ब्रांडिंग के द्वारा तैयार किया जाता हैं। जिसका उपयोग पहले औषधी के रूप में तो किया जाता था, इसके साथ ही अब अदरक का अचार, जूस, अदरक की कैंडी सहित कई प्रकार के उत्पादों का निर्माण किया जा रहा हैं। जिले में हर साल अदरक की खेती के रकबे में जबरदस्त इजाफा हो रहा हैं जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही हैं।

बड़वानी के अदरक से किसानों हो रहे फायदे

- बड़वानी में अदरक का बंपर उत्पादन रहा हैं, जिससे किसानों की आयों में वृद्धि हो रही है।
- एक जिला एक उत्पाद के तहत बड़वानी के अदरक का चयनित किया गया हैं।
- अदरक की फसल ने बड़वानी जिले को एक नई पहचान दिलाई हैं।
- अदक न केवल मसाले के रूप में बल्कि औषधी के रूप में हो रहा हैं प्रयोग
- अदरक से अचार, जूस, अदरक की कैंडी सहित कई प्रकार के उत्पादों का निर्माण हो रहा
- खास तरह की प्रोसीसिंग एंव ब्रांडिंग के द्वारा तैयार होते हैं अदरक के अन्य उत्पाद
- जिले में हर साल बढ़ रहा अदरक की खेती का रकबा

जागत गांव हमार

ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान

खरगोन में कश्मीर जैसी बर्फबारी का नजारा, मुआवजे की आस में किसान

काटकर रखी गई गेहूं की फसल यदि भीगी है तो गेहूं की चमक फीकी पड़ने का अंदेशा जता रहे किसान

भोपाल। जागत गांव हमार

वर्षा ने किसानों के अरमान धुल दिए हैं। कई क्षेत्रों में वर्षा व ओलावृष्टि हुई। प्रतिकूल मौसम से फसलों को व्यापक नुकसान की खबर है। प्रदेश सरकार ने फसलों के नुकसान का सर्वे कराने का निर्देश दिया है। सर्वे शुरू भी हो गया है लेकिन अभी कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। किसानों ने सर्वे का दायरा बढ़ाकर तत्काल राहत देने की मांग की है। इन दिनों गेहूं, चना, मक्का और बाजरा की फसल की कटाई हो रही है और अभी भी कई क्षेत्रों में गेहूं की फसल खड़ी हुई है। ओलावृष्टि और बारिश से गेहूं की फसल खेतों में आड़ी हो गई है। कई जगह बारिश के चलते गेहूं का दाना भी पतला हो गया है।

जानकारी के अनुसार मालवा- निमाड़ अंचल में वर्षा का दौर जारी रहा। शनिवार की रात को हुई वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल खेत में ही गिर गई है। बालियां टूट कर बिखर गई हैं। कटी फसल में भी दाने की गुणवत्ता खराब होने की आशंका बढ़ गई है। कृषि उपसंचालक केसी वास्केल ने बताया कि जिले में 20 फीसद किसान ऐसे हैं जिन्होंने मौसम को देखते हुए फसल नहीं काटी है।

काटकर रखी गई गेहूं की फसल यदि भीगी है तो गेहूं की चमक फीकी पड़ने का अंदेशा रहेगा। बुरहानपुर में सैकड़ों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई है। रविवार सुबह खेतों में पहुंचे किसानों की आंखों से आंसू निकल आए। दल सोमवार से गांवों में जाकर फसलों की स्थिति देखेगा।

किसानों की मेहनत पर पानी फिरा

खरगोन जिले में भी आंधी, बारिश और ओलों ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। बड़वानी जिले में रविवार दोपहर पहाड़ी क्षेत्र में आंधी चली। गांव सेमलेट में आकाशीय बिजली गिरने से तीन गोवंशी की मौत हो गई। मंदसौर के नगरी, कचनारा व लसूड़िया इला में किसान रविवार को बची-कुची फसलों को समेटते रहे। जिला प्रशासन फिलहाल नजरी सर्वे करा रहा है। झाबुआ में कृषि उपसंचालक नगीन रावत का कहना है कि फिलहाल सर्वे को लेकर कोई आदेश नहीं मिले हैं।

खंडवा में फसलें तबाह

खंडवा में तेज बारिश के चलते खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है। यहां भी अधिकतर खेतों में गेहूं की फसलें खड़ी हुई हैं। हालांकि कुछ खेतों में गेहूं की फसल की कटाई हो चुकी है, लेकिन बारिश होने से गेहूं का दाना पतला पड़ गया है। ऐसे में किसानों के सामने अब उसे बेचने की समस्या खड़ी हो जाएगी। किसान संघ के अध्यक्ष सुभाष पटेल ने मांग की है कि सरकार इस ओर ध्यान दें और बारिश और ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान की भरपाई करें। खंडवा के पुनासा, मूंदी, पंधाना, छैगांव सहित अन्य जगहों पर बेमौसम बारिश होने से किसान परेशान है।

खरगोन में मुसीबत

मध्यप्रदेश में खरगोन जिले के कई क्षेत्रों में बे मौसम बारिश ने किसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। वहीं, आदिवासी बहुल ग्रामों में बारिश के साथ जमकर ओला वृष्टि भी हुई है। खरगोन के झिरनिया ब्लॉक में ग्राम काकोडा, हेलापडावा, व मालगांव कोठा में मुसलाधार बारिश के साथ बर्फ नुमा ओले गिरे। ओलों से पटा ग्रामीण इलाका कश्मीर सा हो गया है। सड़क, खेत, घर सभी ओलों से भरे दिखाई दे रहे है। पिछले दो तीन दिनों से खराब मौसम और बारिश के साथ तेज हवाओं की वजह से फसलों का नुकसान हो रहा है, जिस से किसान परेशान हैं।

बैतूल में भी ऐसे ही हालात

यही हाल बैतूल का भी है। बैतूल जिले के दर्जन भर गांव में ओलावृष्टि और बारिश का कहर जारी है। यहां भी ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कई जगह तो बर्फ सड़कों पर सफेद चादर की तरह बिछ गई है। खासकर दामजीपुरा और पाढर इलाके में जमकर ओलावृष्टि होने से अधिक नुकसान हुआ है। बता दें, यहां आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि भी हुई है।

आंवले के आकार के ओले

कटनी में 10 मिनट तक बेर के आकार के ओले गिरे। डिंडौरी जिले के बजाग जनपद, करंजिया के ग्रामीण अंचल में ओलावृष्टि हुई है। गोरखपुर कस्बा सहित आसपास के क्षेत्र में लगभग 10 मिनट तक आंवले के आकार के ओले गिरे। इससे खेत खलिहान में काटकर रखी गई फसलों को नुकसान हुआ है। बोंदर-बजाग मार्ग पर ग्राम गिरवरपुर के पास ओले गिरने से सफेद चादर सी बिछ गई।

पन्ना में तेज बारिश के साथ कई जगहों पर गिरे ओले

पन्ना में ओलावृष्टि हजारों किसानों की फसलें बर्बाद हो गयी है। जिले में तेज बारिश के साथ कई जगहों में ओले गिरे हैं। जिससे किसान की चिंता बढ़ गयी है। अब वह नुकसान से उबरने के लिए सरकार की ओर निहार रहे है। किसानों की फसलें पक कर तैयार थी, और अधिकांश फसलों को काटने की किसान तैयारी कर रहे है। तभी आज तेज बारिश के साथ ओले पड़े हैं। भारी ओलों की बरसात में किसानों की खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं, अजयगढ़ बृजपुर सहित कई क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ ओले पड़े हैं।

किसानों की बड़ी मुश्किलें, खजुराहो में सबसे ज्यादा बारिश

जानकारी के मुताबिक प्रदेश भर में सबसे ज्यादा बारिश खजुराहों मे दर्ज की गई है। यहां पर 1.29 इंच बारिश दर्ज की गई है। एमपी में मार्च के महीने में लगातार बेमौसम बारिश जारी है, जिसके चलते शनिवार को खजुराहो समेत आसपास क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरु हुई और चने और कंचे के आकार के ओले गिरे जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बेमौसम हुई बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हुआ तो वही तेज आंधी तूफान की वजह से ही कई पेड़ भी गिर गए हैं।

नर्मदापुरम में भी मौसम खराब

नर्मदापुरम में भी रविवार की शाम को मौसम ने करवट ली और अचानक तेज हवा के साथ तेज बारिश का दौर देखने को मिला। बारिश से जहां मौसम में ठंडक घुल गई वहीं बारिश में भीगने से बचने के लिए लोग यहां वहां बचते भी नजर आए। बता दें, तीन दिन से रुक-रुक कर बारिश का दौर शहर सहित ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। रात को हुई तेज बारिश के बाद सुबह तेज धूप निकली हुई थी। लेकिन देर शाम मौसम ने करवट बदली और फिर तेज बारिश का दौर शहर में देखने को मिला। दमोह जिले की बात करें तो यहां भी मौसम का मिजाज अचानक बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। दमोह जिले में कई जगहों पर बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। बता दें, कि यहां भी खेतों में कटाई के लिए गेहूं और चने की फसलें तैयार हैं, लेकिन कटाई नहीं होने से यहां भी किसानों को नुकसान होने की आशंका है।

बुरहानपुर में गेहूं, मक्का की फसल खराब

बुरहानपुर जिले के धुलकोट क्षेत्र में भी बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। धुलकोट के गंभीरपुरा क्षेत्र के आसपास के स्थानों में तेज हवा, आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बुरहानपुर और आसपास के इलाकों में आसमान में बादल छाने और हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। इससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन किसानों के लिए आफत आ गई है। यह आफत की बारिश अब किसानों को मुश्किल में डाल रही है। इससे गेंहू, चना, मक्का की फसल बर्बाद हो रही है।

मोटा अनाजः भविष्य के लिए उपयोगी फसलें

डॉ. शालिनी चक्रवर्ती
वरिष्ठ वैज्ञानिक (खादय विज्ञान), कृषि विज्ञान केन्द्र, राजगढ़, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर मप्र

मोटे अनाज अति प्राचीन काल से भारत वर्ष में प्रयुक्त होते आ रहे हैं। मोटे अनाजो के साथ तुलनीय है वरन् कार्बोहाईड्रेट, सूक्ष्म पोषक तत्व तथा फाइटोकेमिकल तत्वो के बहुत अच्छे स्त्रोत हैं। भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाजों के अन्तर्गत सामान्यतः ज्वार, बाजरा, मडुंवा, सॉवा, कुटकी (समई) तथा रागी प्रमुख है।

मोटे अनाज अति प्राचीन काल से भारत वर्ष में प्रयुक्त होते आ रहे हैं। मोटे अनाज अपने अनगिनत पोषण तथा शारीरिक लाभो के कारण न सिर्फ प्रमुख अनाजो के साथ तुलनीय है वरन् कार्बोहाईड्रेट, सूक्ष्म पोषक तत्व तथा फाइटोकेमिकल तत्वो के बहुत अच्छे स्त्रोत हैं। प्रमुख अनाजो की तरह मोटे अनाजों का मुख्य घटक कार्बोहाईड्रेट हैं। मोटे अनाजों के कार्बोहाइड्रेट में 65-70 प्रतिशत स्टार्च तथा 16-20 प्रतिशत गैर स्टार्च कार्बोज होता हैं जिससे तकरीबन 95 प्रतिशत आहारीय रेशों की प्राप्ति होती हैं। ये आहारीय रेशे कब्ज की रोकथाम , रक्त कोलेस्ट्राल को कम करना तथा पाचन के दौरान रक्त ग्लूकोंज के स्तर को नियंत्रित करने आदि में सहायक हैं। मोटे अनाज कई पोषक मूल्यों में गेहूं तथा चावल से भी अधिक बेहतर हैं। जैसे कि मोटे अनाजों में पायी जाने वाली प्रोटीन चावल में पाई जाने वाली प्रोटीन की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाली प्रोटीन हैं। मोटे अनाजों में आवश्यक अमीनो अम्लो की गुणवत्ता गेहूं व मक्का की तुलना में कई अधिक हैं। मोटे अनाजों में प्रमुख विटामिन जैसे थायमिन, राइबोफ्लेविन, फोलिक अम्ल तथा नियासिन आदि भी अच्छी मात्रा में पाये जाते हैं। अनाजो के अन्तर्गत रागी कैल्शियम का उच्चतम स्त्रोत हैं। सारे मोटे अनाज फास्फोरस तथा लौह तत्व के भी अच्छे स्त्रोत माने जाते हैं। लस (ग्लूटिन) गेहूं में पायी जाने वाली एक सरंचनात्मक प्रोटीन हैं। लस की उपस्थिति गेहूं के आटे को लोचदार बनाने लिए उत्तरदायी हैं। परन्तु कुछ लोगो का शरीर इस प्रोटीन को पचा नही पाता तथा सिलिएक रोग से ग्रसित हो जाता हैं। इस रोग में छोटी आंत में सूजन आ जाने से लौह तत्व, फौलिक एसिड, कैल्शियम, नियासिन तथा वसा में घुलनशील विटामिन सहित कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का अवषोषण नहीं हो पाता हैं। यह रोग होने की संभावना 3345 व्यक्तियों में किसी एक व्यक्ति को होती हैं। ऐसे लोगो के लिए जीवन भर लस मुक्त आहार अपनाने का एकमात्र विकल्प हैं मोटे अनाजों को दैनिक आहार में शामिल करना। मोटे अनाजों में लस नही पाया जाता हैं इसलिए लसअसहिष्णु लोगो के लिए मोटे अनाज उपयुक्त होते हैं।

मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए बहुत कम पानी की खपत होती हैं इसलिए सिंचाई तथा बिजली जैसे संसाधनो के लिए सरकार पर निर्भरता भी कम रहती हैं। मोटे अनाजों का उत्पादन कम उर्वरकता वाली भूमि, कम गहरी भूमि तथा कम पानी वाली की उपलब्धता में भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है इसलिए विषाल शुष्क क्षेत्रो के लिए ये एक वरदान है। मोटे अनाजों का उत्पादन कृत्रिम उर्वरकों के उपयोग पर निर्भर नही हैं इसलिए अधिकांष किसान को जैविक खाद ही उपयोग में लाना इससे काफी हद तक सरकार पर उर्वरक सब्सिडी के बोझ को कम किया जा सकता हैं। मोटे अनाजों की खेती प्रणाली के इन सभी आसाधारण गुणों तथा क्षमताओं के बावजूद मोटे अनाजों के उत्पादन क्षेत्र में पिछले कुछ दशको से निरंतर कमी आती जा रही हैं।

मोटे अनाजों का भोजन में उपयोग: जबकी पोषण की दृष्टि से मोटे अनाज प्रमुख अनाजों की तुलना में बेहतर हैं तब भी अभी तक इन फसलों का भोजन में उपयोग परंपरागत उपभोक्ताओं तक ही सीमित हैं तथा मुख्यता गरीब वर्ग के लोगो द्वारा ही खाया जाता हैं। मोटे अनाजों को खासतौर पर धार्मिक कार्यो जैसे व्रतों के दौरान सबसे अधिक याद किया जाता हैं।

गेहूं भारतीय कृषि प्रणाली के लिए नया हैं परन्तु सरकार के संरक्षण तथा प्रचार के कारण गेहूं के प्रसंस्कृत खाद् पदार्थ आसानी से उपलब्ध होने के कारण यह लोगो में ज्यादा लोकप्रिय हो गया तथा मोटे अनाज उतने लोकप्रिय नही हो पाये। मोटे अनाजों की अलोकप्रियता के कई कारण रहे हैं -

1. मोटे अनाजों द्वारा होने वाले स्वास्थ्य लाभों के प्रति आम आदमी की उदासीनता/अज्ञानता।
2. मोटे अनाजों को खाने योग्य बनाने के लिए उपयुक्त प्राथमिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का अभाव।
3. मोटे अनाजों से तुरन्त खाए जाने वाले मूल्य सवर्धित खाद्य सामग्री बनाने की प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का अभाव।
4. मोटे अनाजों की बाहरी सतह कठोर होने के कारण इसको अन्य प्रमुख अनाजों की तरह पकाकर नरम नहीं किया जा सकता हैं।
5. मोटे अनाजों में एक विशेष प्रकार का स्वाद तथा गंध होती हैं।
6. इसके अतिरिक्त मोटे अनाजों में गेहूं की तरह लस (ग्लूटिन) नही पाया जाता हैं अतः इससे गेहूं की तरह पतली रोटी /चपाती तैयार नही की जा सकती हैं।

उक्त कारणो से मोटे अनाजों का उपयोग समाज के गरीब वर्ग तक ही सीमित बना हुआ हैं। हॉलाकि, मोटे अनाजों के प्रसंस्करण सम्बंधित कई अध्ययनों के प्रदर्शन से इसके उपयोग को बढ़ावा मिला हैं। परन्तु मोटे अनाजों को शहरी तथा गैर परम्परागत आबादी के बीच अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए तथा मोटे अनाजों के विविध उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निरन्तर प्रयास की आवश्यकता हैं।

पशुओं में मूत्राश्मरता (गुर्दे की पथरी), उपचार एवं नियंत्रण

» डॉ. ज्योत्सना शक्करपुडे
» डॉ. मधु शिवहरे
» डॉ. कविता रावत
» डॉ. अर्चना जैन
» डॉ. नीतू राजपूत
» डॉ. दानवीर सिंह यादव
» डॉ. अशोक पाटिल
» डॉ. नरेश कुरेचिया
पशु जन स्वास्थ्य एवं महामारी विज्ञान विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय,महू

कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, फास्फोरस तथा विटामिन आदि का आहार में असंतुलन होने से मूत्राश्मरता रोग होता है। कैल्शियम और फास्फोरस के लगभग समान अनुपात वाले उच्च-केंद्रित अनाज आहार, लेकिन मैग्नीशियम, पोटैशियम और फास्फोरस में बहुत अधिक आहार को कैलकुली के बनने का कारक माना जाता है। रोग की प्रथम अवस्था में कोलाइडी मैट्रिक्स बन जाती है, इसके बाद खनिज लवण का अवक्षेपण होता है, जिससे मूत्र के निष्कासन में बाधा आती है और यह रोग उत्पन्न हो जाता है।

इस रोग में पशु के मूत्र में म्यूकोप्रोटीन 3 से 4 प्रतिशत पाया जाता है । मूत्र में अन्य खनिज लवण क्लोराइड, सल्फेट, फास्फेट, सिलिकेट तथा कार्बोनेट होते है। ये सब मैग्नीशियम, सोडियम, पोटैशियम तथा कैल्शियम लवण होते है। साधारण तथा सामान्य स्वास्थ्य वाले पशु में क्लोराइड एवं सल्फेट म्यूकोप्रोटीन में अवक्षिप्त हो जाते है और मूत्र द्वारा निष्कासित हो जाते है । आहार में इन दोनों की कमी से मैग्निशियम फास्फेट और अमोनिया फास्फेट म्यूकोप्रोटीन में अवक्षिप्त हो जाते हैं क्योंकि यह दोनों अविलेय होते हैं इसलिए यह कैलस बन जाते हैं इनका निष्कासन नहीं हो पाता और इनके ऊपर सिलिकेट लवण अवक्षिप्त होते जाते हैं, कैलस का आकार भी बढ़ जाता है।

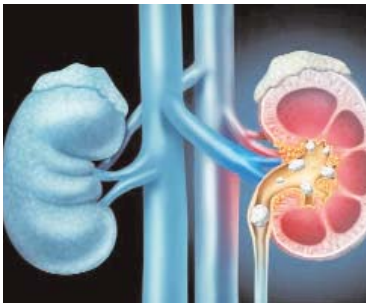

आहार में फास्फेट की अधिकता, विटामिन ए की कमी कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं पोटैशियम का असंतुलन, आवश्यकता से अधिक जल पिलाना, जल में अधिक खनिज लवण पाए जाने आदि के कारण यह रोग होता है । पशुओं को आवश्यकता से अधिक मात्रा में दाना खिलाने पर मूत्र का पीएच मान कम हो जाता है, इसकी वजह से कैलस बनने प्रारंभ हो जाते हैं। कुछ चरागाह में मॉलीब्डेनम की कमी होने पर वहां पशुओं के शरीर में जैंथीन प्रकार के कैलस बनते हैं, बरसीम खाने से भेड़ों के वृक्क में कैलस बन जाते हैं। कम फाइबर वाले आहार पर बकरियां अधिक संवेदनशील हो सकती हैं, क्योंकि लार का उत्पादन कम हो जाता है। चूंकि लार में फॉस्फोरस का उच्च स्तर होता है, इसलिए शरीर में फॉस्फोरस का निर्माण हो सकता है।

नर और मादा दोनों प्रकार के पशुओं के वृक्क में कैलस बनते हैं नर का मूत्र मार्ग तिरछा होने से कैलस छोटे आकार के बनने पर मूत्र द्वारा सुगमता से बाहर निकल सकते हैं पर अधिक बड़े आकार वाले कैलस की निकासी में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसके विपरीत मादा का मूत्र मार्ग सीधा व बड़ा होने के कारण वृक्क में किसी भी प्रकार के कैलस सुगमता से निष्कासित हो जाते हैं मूत्र मार्ग में जहां भी यह कैलस उलझ जाते हैं वहां घाव हो जाता है व सूजन आ जाती है जिससे मूत्र निकासी में बाधा आ जाती है ऐसी स्थिति में मूत्राशय के फटने की संभावना रहती है और मूत्र एकत्रित होने से मृत्यु भी हो सकती है ।

वृक्क में कैलस होने के लक्षण: पशु पेट में दर्द होने के लक्षण प्रकट करता है बार-बार पूंछ हिलाता है, पशु मूत्र निकासी का प्रयास करता है और ऐसा करने में असमर्थ होता है, मूत्र में जलन, मूत्र में रक्त आना, बेचैनी, भूख कम लगना, मूत्र मार्ग फटना आदि लक्षण दिखाई देते है एवं उसके रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है।

उपचार- इस रोग में उचित एंटीबायोटिक के साथ साथ पर्याप्त मात्र में पानी देना चाहिए। यूरिया का स्तर रक्त में नियंत्रित करने के लिए दवाई दे सकते है, दर्द निवारक दवाइयां भी दी जा सकती है। गंभीर स्थिति में शल्य चिकित्सा की आवश्यकता पद सकती है। ऐसे रोगी पशुओं को 2 प्रतिशत क्लोराइड या आधा प्रतिशत अमोनिया क्लोराइड जल में घोलकर पिलाना चाहिए।

नियंत्रण

-अच्छा स्वादिष्ट चारा खिलाएं।
-आहार और प्रबंधन में अचानक बदलाव नहीं करना चाहिए।
-हर समय पर्याप्त पानी का सेवन सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें कि पानी साफ है, सभी पशुओ को एक साथ पीने के लिए पर्याप्त कंटेनर हैं। कठोर पानी को पशु के पीने के लिए उपयोग न करें।
-कैल्शियम फास्फोरस अनुपात के साथ एक संतुलित आहार खिलाएं।

जरा रहम करो मैं किसान हूं...

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह

तुम गरज-चमक कर आते हो,
मेरे अरमानों पर ओले बरसाते हो।

मेरी पूरी साल की मेहनत और कमाई पर,
पल भर में वज्रपात गिरा जाते हो।

आखिर मेरी तुमसे दुश्मनी ही क्या है.....
कि जब खेतों में मेरी फसल पक्की खड़ी हो, तब ही तुम अपनी औकात दिखाते हो।

जब होती जरूरत मुझे तुम्हारी,
तब तुम दूर-दूर तक कहीं नजर नहीं आते हो।

आखिर इतना भाव क्यों खाते हो,
इतना सारा एटीट्यूट कहां से लाते हो।

क्या मैं ही कमजोर हूं इस जहान में?
क्या मैं किसान हूँ! इसलिए मुझे तड़पाते हो।

मुझे बताओ मेरा यह गुनाह हैं क्या,
कि मैं पूरी दुनिया के प्राणियों का पेट भरता हूं।
खाद्यान्न, दलहन, तिलहन से लेकर फल-सब्जी उगाकर देता हूं।

यह मानवता का काम हैं फिर भी,
तुम इतना पक्षपात क्यों निभाते हो।

तुम तभी गरज-चमक कर आते हो जब मेरी फसल पक्की खड़ी हो खेतों में,
तुम तब ही ओले बरसाते हो।

अतिवृष्टि का खेल दिखा कर मेरे अरमानों को चूर-चूर कर जाते हो।

हे मालिक- जरा रहम करो मैं किसान हूं।

श्री अन्न वर्ष 2022-23 में घटा मिलेट का उत्पादन

श्री अन्न वर्ष 2022-23 में घटा मिलेट का उत्पादन

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

सरकार और कृषि मंत्रालय श्री अन्न (मिलेट्स) के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की समय-समय पर काफी सारी योजनाओ व नीतियों को गठन कर रही हैं। इसके अलावा किसानों को मिलेट्स की खेती करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार की इतनी कोशिशों के बाद भी मिलेट्स का उत्पादन पिछले पांच वर्षों की तुलना में घटा हैं। वर्ष 2017-18 में श्री अन्न का कुल उत्पादन 164.36 लाख टन था और अब वर्ष 2022-23 में श्री अन्न का उत्पादन घट कर 159.09 लाख टन रह गया हैं। कुछ राज्यों में श्री अन्न का उत्पादन बढ़ा अवश्य है, लेकिन पूरे देश में श्री अन्न की उत्पादकता और उत्पादन में गिरावट आई है।

मिलेट उत्पादन बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे उप-मिशन- केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया कि मिलेट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय 2018-19 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएस) के तहत उत्तर प्रदेश , महाराष्ट्र एंव मध्यप्रदेश राज्य सहित 14 राज्यों के 212 जिलों में पोषक अनाज (मिलेट) पर एक उप-मिशन चला रहा है।

एनएफएसएम के तहत सहायता प्रदान कर रहे

एनएफएसएस-पोषक अनाज के तहत, फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकयों, फसल प्रणाली आधारित प्रर्दशनों, नई जारी किस्मों व संकरों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन वितरण, फसल मौसम के दौरान प्रशिक्षण के द्वारा किसानों को श्री अन्न की खेती के फायदे और लाभों की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा मीडिया के माध्यम से भी किसानों को श्री अन्न की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कृषि विभाग द्वारा पोषक अनाजों के लिए किसान उत्पादक संगठनों का गठन , पोषक अनाजों के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) और सीड हब की स्थापना के लिए भी एनएफएसएम के तहत सहायता प्रदान की जाती है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में कुल मिलेट उत्पादन का राज्य-वार विवरण नीचे सारणी में दिया गया है- मिलेट (ज्वार, बाजरा, रागी और छोटा बाजरा) (लाख टन में)

राज्य/संघ	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
आंध्रप्रदेश	4.45	3.02	5.14	5.41	3.59	3.53
गुजरात	11.16	10	9.9	10.92	11.79	3.98
हरियाणा	7.46	9	10.35	13.67	11.32	10.75
कर्नाटक	27. 39	17.62	25.56	25.69	20.54	22.39
मध्यप्रदेश	14.69	8.51	8.96	10.24	11.81	11.72
महाराष्ट्र	24.03	13.19	24.29	25.14	23.05	19.59
राजस्थान	40.62	42.88	51.47	51.56	42.8	55.02
तमिलनाडु	9.27	8.73	10.17	9.05	7.65	7.61
तेलंगाना	0.84	0.72	1.39	1.66	1.23	0.96
उत्तरप्रदेश	20.15	19.67	21.72	22.98	22.26	20.05
उत्तराखंड	2.17	1.8	1.91	2.01	2	1.82
अन्य	2.06	1.96	1.75	1.88	1.95	1.68
कुल	164.36	137.11	172.61	180.21	160	159.09

गतिविधि के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार

भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष (आईवाईएम)- 2023 में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने, खपत, निर्यात, मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने ब्रांडिंग, स्वास्थ्य लाभ के लिए जागरूकता लाने के लिए कई रणनीतियों पर काम कर रही है। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारों और भारतीय दूतावासों द्वारा उत्पादन और मांग बढ़ाने के लिए मिलेट्स के संबंध में जागरूकता लाने संबंधी मासिक गतिविधि के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई हैं। इसके अलावा, सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य दिलवाने के लिए बाजरा और रागी जैसे मिलेट्स के लिए न्यूतम समर्थन मूल्य भी निर्धारित किए हैं।

अभी तक 15 लाख किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन

प्रदेश सरकार ने 2023 में 70 लाख टन गेहूं खरीदी का रखा टारगेट

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने 25 मार्च से एमएसपी पर रबी फसल की खरीद शुरू करने का फैसला किया है। सरकार ने इस वर्ष 70 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। वहीं, अभी तक लाखों किसानों ने गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। मध्य प्रदेश पंजाब के बाद दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। जानकारी के मुताबिक, आधिकारिक तौर पर गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। वहीं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से ही शुरू हो रही है। केंद्र सरकार ने इस बार 10 राज्यों से 341.5 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछले आरएमएस 2022-23 के दौरान 189 लाख टन गेहूं की वास्तविक खरीद से 90 प्रतिशत अधिक है।

जानकारी के मुताबिक, आधिकारिक तौर पर गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। वहीं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से ही शुरू हो रही है। केंद्र सरकार ने इस बार 10 राज्यों से 341.5 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछले आरएमएस 2022-23 के दौरान 189 लाख टन गेहूं की वास्तविक खरीद से 90प्रतिशत अधिक है। वहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि प्रदेश के अंदर गेहूं खरीद चालू होने से पहले सभी तरह की तैयारियां पूरी कर जी जाएं। किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं, अधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष लगभग 15 लाख किसानों ने अभी तक पंजीयन कराया है। पिछले साल की तुलना में तीन चौथाई रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। करीब 20 लाख से अधिक किसानों के रजिस्ट्रेशन कराने की संभावना है।

सभी तरह की तैयारियां पूरी कर जी जाएं

वहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि प्रदेश के अंदर गेहूं खरीद चालू होने से पहले सभी तरह की तैयारियां पूरी कर जी जाएं। किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं, अधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष लगभग 15 लाख किसानों ने अभी तक पंजीयन कराया है। पिछले साल की तुलना में तीन चौथाई रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। करीब 20 लाख से अधिक किसानों के रजिस्ट्रेशन कराने की संभावना है।

कहां कब से शुरू होगी खरीद

जानकारी के मुताबिक, उज्जैन, भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम संभाग में 25 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरू होगी, जबकि शहडोल, सागर, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर और चंबल संभाग में एक अप्रैल से खरीदी शुरू की जाएगी। इसके लिए प्रदेश में 4223 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। बारदानों में लगभग 3 लाख गांठों की अनुमानित आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था की गई है। वर्तमान में उपलब्ध बारदानों से लगभग 70 लाख मीट्रिक टन की खरीद संभव है। जानकारी के मुताबिक, उज्जैन, भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम संभाग में 25 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरू होगी, जबकि शहडोल, सागर, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर और चंबल संभाग में एक अप्रैल से खरीदी शुरू की जाएगी। इसके लिए प्रदेश में 4223 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। बारदानों में लगभग 3 लाख गांठों की अनुमानित आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था की गई है। वर्तमान में उपलब्ध बारदानों से लगभग 70 लाख मीट्रिक टन की खरीद संभव है।

केंद्र सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत

अब उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी में नहीं चलेगी कैंची

नई दिल्ली। रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री भगवंत खुबा ने लोकसभा में अपने लिखित जवाब में कहा है कि, किसानों पर उर्वरक सब्सिडी कम करने के प्रभाव को समझने के लिए अभी तक ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया। इस तरह केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि उर्वरकों पर सब्सिडी में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्री ने एक और जवाब में बताया है कि, केंद्र सरकार के पास पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत उर्वरकों की दरों को कंट्रोल करने की कोई योजना नहीं है।

सरकार कृषकों को सस्ते रेट पर यूरिया व गैर-यूरिया उर्वरक दोनों पर सब्सिडी मुहैया कराती है। उन्होंने बताया कि किसानों को अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य 242 रुपये/बैग 45 किग्रा (नीम कोटिंग और लागू करों को छोड़कर) पर यूरिया प्रदान किया जाता है।

सब्सिडी 42 हजार करोड़ होने का अनुमान

फाइनान्शियल इयर 2022-23 में पी एण्ड के उर्वरकों के लिए सब्सिडी 42 हलार करोड़ रुपए होने का अनुमान है। पंजीकृत पी एण्ड के उर्वरक विनिर्माताओं/आयातकों को सब्सिडी मिलती है जो कृषकों को सब्सिडी रेट पर इन उर्वरकों को उपलब्ध कराते हैं। किसानों के लिए उर्वरक कई मायनों में आवश्यक होता है। उपज बढ़ाने और मिट्टी में पोषक तत्वों का सही संतुलन बनाकर बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करने में उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सही समय पर उर्वरकों के सही इस्तेमाल से फसल वृद्धि होती है, उच्च गुणवत्ता वाले फ़सल की उपज उर्वरकों के उपयोग से सुनिश्चित की जा सकती है, उर्वरक पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इनसे पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है और उनके जड़ों के विकास में मदद मिलती है। इसके अलावा उर्वरक कृषि में कई तरह से अहम जगह रखते हैं।

46 कीटनाशकों के निर्माण, आयात पर प्रतिबंध

नई दिल्ली। कृषि मंत्रालय ने अब तक देश में आयात, विनिर्माण या उपयोग के लिए 46 कीटनाशकों और 4 कीटनाशक विनिर्मितियों पर प्रतिबंध लगाया है या उन्हें चरणबद्ध तरीके से हटा दिया है। इसके अलावा 8 कीटनाशकों के पंजीकरण को वापस ले लिए गया है और 9 कीटनाशकों को प्रतिबंधित उपयोग के तहत रखा गया है। ये जानकारी केन्द्रीय कृषि मंत्री ने गत दिवस लोकसभा में दी। कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा (5) के तहत गठित पंजीकरण समिति (आरसी) देश में कीटनाशकों के उपयोग के लिए उनकी सुरक्षा और प्रभाव उत्पादकता का मूल्यांकन करने के बाद उनका पंजीकरण करती है। पंजीकरण समिति कीटनाशकों का पंजीकरण करते समय लेबल पर खुराक, फसलों, एहतियाती उपायों, प्रतिषेधक आदि का विवरण देती है। यदि पंजीकृत कीटनाशक लेबल और पदक के अनुसार उपयोग किए जाते हैं।

वर्ष 2011 में 1 हजार वर्ग मीटर के क्षेत्र में नर्सरी बनाकर शुरुआत हुई

जिला एक उत्पाद योजना लागू होने के बाद हरी और लाल मिर्च का रकबा बढ़ा

खरगोन के किसान ने 4 साल में बेचे 5 करोड़ मिर्च के पौधे, कई राज्यों में तेजी से बढ़ी मांग

खरगोन। जागत गांव हमार

कहते हैं कि किसी काम को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उस कार्य को पूरा करने में जुट जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी बड़वाह में सिरलाय के युवा किसान और नर्सरी संचालक जितेंद्र पटेल की है। सब्जी की खेती करने वाले युवा किसान जितेंद्र किसी नर्सरी से सब्जियों की पौध लेकर आए तो उन्हें गुणवत्तापूर्ण और आवश्यकता अनुसार पौध नहीं मिली तो उन्होंने भी किसानों को ऐसे घाटे से बचाने के लिए पूरी लगन और दिल लगाकर नर्सरी की शुरुआत हुई। वर्ष 2011 में 1 हजार वर्ग मीटर के क्षेत्र में नर्सरी बनाकर शुरुआत हुई। आज उनकी नर्सरी 13.50 एकड़ में फैल चुकी है। हालांकि नर्सरी में सब्जी, अर्नामेंट और फलों के भी पौधे तैयार होते है। लेकिन इन दिनों कुछ वर्षों से मिर्च की पौध की मांग बढ़ने से इस पर ज्यादा फोकस होकर काम करने लगे है। जितेंद्र बताते है कि पिछले वर्ष उन्होंने 25 मिर्च की किस्मों के 50 किलो बीज की पौध तैयार की थी। इस बार उन्होंने 75 किलो मिर्च के बीज की पौध की तैयारी की है। उन्होंने करीब 4 वर्षों में 4 से 5 करोड़ मिर्च की पौध तैयार कर बेंची है। उनका कहना है कि एक जिला एक उत्पादन में चिन्हित होने से मिर्च पौध में वृद्धि हुई है। करीब 13 वर्षों में जितेंद्र पटेल ने अपनी नर्सरी को हाइटेक बनाकर अपने व्यावसाय को सिर्फ मप्र में सीमित नहीं रखा। उनकी नर्सरी की पौध की मांग अब राजस्थान के अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में होने लगी है।

हाइटेक नर्सरी बनाने की कोशिश में मिला शासन का सहयोग

जितेंद्र अपनी पूरी लगन के साथ नर्सरी के काम मे बढ़ने लगे तो इसे हाइटेक बनाने की इच्छा जागी। ऐसी स्थिति में शासन से उनको पूरा सहयोग मिला। उद्यानिकी विभाग के उपसंचालक गिरवाल ने बताया कि जितेंद्र को सबसे पहले 2013-14 में उद्यानिकी विभाग की बागवानी मिशन में 4000 वर्ग मीटर में 14 लाख 20 हजार के अनुदान पर शेडनेट हॉउस प्रदान किया। इसके बाद वर्ष 2019-20 में राज्य योजना में उनकी पत्नी और उनके भाई के नाम पर अलग-अलग प्रकरण में कुल 7500 वर्ग मीटर में पॉली हॉउस और शेडनेट हॉउस के लिए 28 लाख 37 हजार 920 रुपये का अनुदान मिला। इसके बाद जितेंद्र ने अपनी नर्सरी को हाइटेक बनाने की दिशा में एक से एक सफल प्रयोग कर एक जिला एक उत्पाद की फसल को बढ़ावा देने में योगदान दे रहे हैं।

प्रदेश में ऋण स्वीकृति सबसे आगे खरगोन में मप्र शासन द्वारा वर्ष 2021 में जिले में मिर्च के उत्पादन और जलवायु को देखते हुए मिर्च की फसल को एक जिला एक उत्पाद फसल के रूप में चुना। इसके बाद कई योजनाओं से किसानों और युवाओं को इस दिशा में रोजगार और मिर्च का व्यवसाय से जोड़ने के लिए शासन की योजनाओं से उद्योग और इससे जुड़े व्यवसाय की शुरुआत हुई। खरगोन पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) में प्रकरण स्वीकृत कर कराने के मामले में प्रदेश में सबसे आगे है। यहां अब तक 92 प्रकरणों को स्वीकृति मिली है और 40 को ऋण दिया गया है। साथ ही सबसे अधिक 481 कुल आवेदन प्राप्त कर 468 प्रस्तुत किये गए। खरगोन में मिर्च के पावडर या पेस्ट बनाने के 10 नए खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग प्रारंभ हुए हैं।

मिर्च का चुनाव होने के बाद बढ़ा लाल और हरी मिर्च का रकबा

उद्यानिकी उपसंचालक केके गिरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि एक जिला एक उत्पाद में मिर्च फसल का चुनाव होने के बाद किसानों में मिर्च की खेती के प्रति रुझाव बढ़ा है। वर्ष 2017-18 और 2018-19 में हरी मिर्च का रकबा 525 हेक्टेयर, 2019-20 में 616 हेक्टेयर, 2020-21 में 1012, 2021-22 में 1096 हेक्टयर रकबे में हरी मिर्च लगाई गई। जबकि लाल मिर्च के रकबे की बात करे तो 2017-18 में 32150 हेक्टेयर रकबे के बाद वर्ष 2018-19 में रकबा कम होकर 25369 हेक्टेयर रह गया। इसके बाद अगले वर्ष 2019-20 में और कम होकर 23280 हेक्टेयर रकबा रहा। जबकि एक जिला एक उत्पाद में मिर्च को चिन्हित करने के बाद अगले वर्ष 2020-21 में रकबा बढ़कर दो गुने से ज्यादा 49052 हेक्टेयर हुआ इसके अगले वर्ष रकबा और बढ़कर 51350 हेक्टेयर हो गया।

मिलेट प्रोग्राम के अंतर्गत कोदो कुटकी के उत्पादों को दिया जा रहा प्रोत्साहन

बालाघाट। स्थानीय आदर्श सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र परसवाड़ा में मिलेट प्रोग्राम के अंतर्गत कोदो कुटकी से बनी उत्पादों के संबंध में प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया उक्त प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर के रूप में बैहर ब्लॉक से जुड़ी दीदियों ने प्रशिक्षण प्रदान किया प्रशिक्षण में बैहर बिरसा परसवाड़ा की दीदियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के दौरान कोदो कुटकी से बनने वाले विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित भी किया गया जिसमे कोदो से बनी ईटली, ढोकला, खुरमी,चावल, कुटकी के लडडू एवं अन्य कोदो कुटकी से बने व्यंजन तैयार किया गया। ताकि ग्रामीण क्षेत्रो में कोदो कुटकी को बढ़ावा दिया जा सके कार्यक्रम पूरे प्रदेश में मिलेट प्रोग्राम के अंतर्गत मनाया जा रहा है जिसमें ग्राम स्तर पर ऐसे उत्पाद जो प्राचीन संस्कृति से जुड़े हैं। प्राचीन लोग खाते आ रहे हैं जो कि औषधि युक्त होते ऐसे उत्पादों को शासन द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में संगम महिला आजीविका संकुल संगठन परसवाड़ा की अध्यक्ष कुंता चौधरी एनआरईटीपी मीरा पटेल एनआरईटीपी परसवाड़ा इकबाल कुरैशी परसवाड़ा ललिता बिसेन बैहर से प्रवीण उपस्थित रहीं।

फल अनुसंधान केंद्र कुठुलिया में छात्र-छात्राओं को पढ़ाया पाठ

मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षण प्राप्त किया

रीवा। जागत गांव हमार

कृषि महाविद्यालय रीवा मप्र के अधिष्ठाता प्रो एस के पयासी के मार्गदर्शन में लाभदायक कीट प्रबंधन विषय के अंतर्गत मधुमक्खी पालन एवम प्रबंधन पर छात्र एवम छात्राओं ने प्रैटिकल के माध्यम से जानकारी प्राप्त किया। डॉ. अखिलेश कुमार विभागाध्यक्ष, कीट विज्ञान विभाग, कृषि महाविद्यालय रीवा द्वारा फल अनुसंधान केंद्र कुठलिया में स्थापित मधुमक्खी पालन इकाई का छात्र छात्राओं को भ्रमण कराया गया, जिसमें बीएससी कृषि तृतीय वर्ष के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। डॉ. कुमार ने बताया कि मधुमक्खी एक समाजिक कीट है जिसके द्वारा लगभग सभी फसलों में 2 प्रतिशत से लेकर 335 प्रतिशत तक पर परागण से उत्पादन एवम गुणवत्ता में वृद्धि होती है। फसलों एवं फलों में मधुमक्खी से 80 से 85 प्रतिशत पर परागण होता है साथ ही साथ इससे सह उत्पाद जैसे मधु, रॉयल जेली, प्रोपोलिस, वैक्स, परागकण, विष प्राप्त होता है जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के रोगो में दवाओं में किया जाता है। मधुमक्खी पालन एक उत्तम व्यसाय है। मधुमक्खी पालन के लिए वर्ष भर के लिए प्राप्त भोज्य पदार्थ के लिए फसल चक्र अपनाना पड़ता है जिससे हमेशा परागकण व पराग रस प्राप्त होता रहे। प्रायोगिक तौर पर छात्रों ने मधुमक्खी की विभिन्न प्रजातियों, जीवन चक्र एवम बॉक्स में रहने वाले रानी मक्खी, नर मक्खी, एवं श्रमिक मक्खियों के साथ उनके प्राकृतिक शत्रुओं के व्यस्थाओं के विषय में बारीकी से जानकारी हासिल की। साथ ही साथ छात्रों ने ये भी जाना कि गांव में लगे मधुमक्खियों के छत्ते को कोई हानि न पहुंचाते हुए मधु को निकालकर उनके जीवन को सुरक्षित रखा जा सकता है जिससे फसलों के पर परागण में कोई रुकावट ना आ सके। इस अवसर पर रीवा जिले प्रगतशील मधुमक्खी पलक अरूण कुमार द्विवेदी, विंध्या बी केयर, पिपरी, बैकुंठपुर, सिरमौर, रीवा के डायरेक्टर भी उपस्थित रहे जो कि मधुमक्खी पालन में कृषि विज्ञान केंद्र रीवा से प्रशिक्षण प्राप्त कर इस व्यवसाय से जुड़े है जिनके द्वारा विंध्य में प्रथम मधु प्रसंस्करण इकाई स्थापित की गई है जिसके माध्यम से कच्ची मधु की प्रोसेसिंग की जाती है।

आहार प्रदर्शनी के दौरान पौध आधारित युग के उषाकाल विषयक कांफ्रेंस को कृषि मंत्री ने किया संबोधित

भविष्य की जरूरतों को पूरा करने पौध आधारित खाद्य अहम विकल्प

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

भविष्य में खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत विकल्प में पौध आधारित आहार पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित आहार प्रदर्शनी के दौरान पौध आधारित युग के उषाकाल विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्लांट बेस्ड फूड्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (पीबीएफआईए) द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पौध आधारित खाद्य वक्त की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही रोजगार के अवसर सृजित करने और कृषि क्षेत्र को भी बल देने वाला है। जो चुनौतियां कृषि के सामने आ रही हैं, उनके मद्देनजर पौध आधारित आहार वैकल्पिक महत्वपूर्ण कदम है।

केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि भविष्य में जरूरत पड़ने वाले विकल्पों को अगर हम अभी से तैयार कर लेंगे तो आने वाले समय में संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। वर्तमान व भविष्य की चुनौतियों से हम अच्छी तरह से अवगत हैं, खाद्य सुरक्षा इन्हीं में से एक है। आने वाले समय में देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, उस समय तक आबादी भी बढ़ जाएगी, वहीं आधुनिक

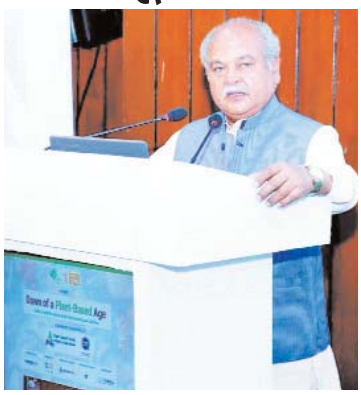

व विकसित भारत के लिए हो रहे अधोसंरचनात्मक विकास, बड़ी संख्या में नई रेल लाइनों को बिछाना, विश्वस्तरीय नेशनल हाईवे बनाना जैसे कार्यों के कारण खेती का रकबा कम होने की संभावना को भी देखना होगा। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के महान उद्देश्य को पूरा करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार तेजी के साथ राज्य सरकारों के साथ मिलकर जुटी हुई है। वर्ष 2050 तक कितने खाद्यान्न की आवश्यकता हमें रहेगी व दुनिया की अपेक्षा हमसे कितनी बढ़ेगी, इस पर अभी से विचार करने की आवश्यकता है। इस दिशा में केंद्र सरकार अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने समग्र व संतुलित विकास की कल्पना को साकार करने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कदम बढ़ाए हैं। कृषि में लोगों की रूचि निरंतर बढ़े, यह भी हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी हमेशा आग्रह करते हैं कि कृषि क्षेत्र में निजी निवेश आना चाहिए, नई तकनीकें आना चाहिए, काम सरल होना चाहिए और किसानों को मुनाफा ज्यादा मिलना चाहिए, इससे आने वाली पीढ़ी कृषि की ओर आकर्षित होगी। किसान खेती का आधार है, यह बात समझना होगी। किसानों को फायदा व प्रतिष्ठा देना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि वह खेती में रूके, देश का पेट भर सके और दुनिया की अपेक्षा को भी पूरा कर सकें। सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाओं द्वारा इस दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

पोषक दृष्टि से भी विकल्प तैयार करना जरूरत

तोमर ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के साथ ही पोषक दृष्टि से भी विकल्प तैयार करना समय की जरूरत है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। श्री अन्न का उत्पादन-उत्पादकता बढ़े, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, निर्यात भी बढ़े, इससे बने पदार्थों को भोजन की थाली में पुनः प्रतिष्ठापूर्ण स्थान मिले, इसलिए यह वर्ष मनाया जा रहा है। इससे पोषक तत्वों का आहार बढ़ेगा, किसानों को फायदा होगा व रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कार्यक्रम में पीबीएफआईए के पदाधिकारी संजय सेठी, एपीडा के सचिव डा. सुधाशु, आईटीपीओ के रजत अग्रवाल भी मौजूद थे।

भारत में पहली बार डिजिटल रूप से सहायता प्राप्त यात्रा में वेयरहाउस रिसिप्ट फाइनेंसिंग का शुभारंभ

एलएंडटी फाइनेंस ने लॉन्च किया वेयरहाउस रिसिप्ट फाइनेंसिंग

भोपाल/मुंबई। जागत गांव हमार

एलएंडटी फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड की सब्सिडियरी और प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से एक एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड ने वेयरहाउस रिसिप्ट फाइनेंसिंग लॉन्च किया है, जो एग्री-कमोडिटी के एवज में लोन सुविधाओं के लिए अपनी तरह का पहला डिजिटल-सहायता प्राप्त तरीका है। डब्लूआरएफ लोन सिक्योर करने के लिए कोलैटरल (लोन के बदले में गिरवी या सिक्योरिटी रखना) के रूप में कमोडिटी के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है। पैनल में शामिल कोलैटरल मैनेजर द्वारा व्यावसायिक रूप से प्रबंधित गोदामों में कमोडिटीज का संग्रहण किया जाता है। इस व्यवस्था के तहत कमोडिटीज की गुणवत्ता और मात्रा की जांच की जाती है, जिसके आधार पर किसानों, व्यापारियों और प्रॉसेसर्स यानी प्रसंस्करणकर्ताओं को कोलैटरल मैनेजर द्वारा रसीद जारी की जाती है। इसके बाद रसीद का उपयोग एलटीएफ से लोन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कोलैटरल के रूप में किया जा सकता है।

इन 4 राज्य के ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा

वेयरहाउस रिसिप्ट फाइनेंसिंग 4 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा और इस उत्पाद की पेशकश के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। वर्तमान में, ये सुविधाएं बाजार द्वारा पारंपरिक तरीके से पेश की जाती हैं जो मुख्य रूप से प्रकृति में मैनुअल हैं। वहीं प्रत्येक लोन आवेदन को स्वीकृत होने में 7-10 दिन लगते हैं। इस उत्पाद के लॉन्च के साथ, ग्राहकों को मोबाइल एप्लिकेशन प्लैनेट के माध्यम से लोन आवेदन दाखिल करने के 24 घंटों के भीतर मंजूरी प्राप्त करने और अपने लोन से संबंधित सभी जानकारी रखने का अनुभव प्राप्त होगा।

किसान, व्यापारी और प्रोसेसर उठा सकते हैं लाभ

किसान, व्यापारी और प्रोसेसर 1 लाख रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच की राशि के लिए आकर्षक ब्याज दरों पर निकटतम एलटीएफ शाखा में इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। स्वीकृत राशि योग्यता या पात्रता जांच और लोन मार्जिन रेंज पर आधारित होगी। वहीं स्वीकृत राशि गुणवत्ता मानकों के आधार पर कमोडिटी के बाजार मूल्य के 25 फीसदी से 30 फीसदी के बीच होगी। एलएंडटी फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ दीनानाथ दुभाशी ने वेयरहाउस रिसिप्ट फाइनेंसिंग के लॉन्च पर कहा कि हमारा लक्ष्य 2026 तक या उससे पहले एक शीर्ष-स्तरीय, ग्राहक-केंद्रित, डिजिटल रूप से सक्षम खुदरा वित्त कंपनी बनना है। उसी के अनुरूप, हम अपने ग्राहकों को उन उत्पादों के साथ जोड़ने के लिए लगातार काम कर रहे हैं जो उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल हों और साथ ही उनकी आवश्यकता के समय उपलब्ध हों। एलटीएफ हमारी ओर से एक ऐसी पेशकश है जो बिना किसी फोरक्लोजर चार्ज के त्वरित डिस्बर्समेंट और लचीले पुनर्भुगतान की सुविधा देती है। भारत में रबी फसल की बुवाई का मौसम इस फसल वर्ष में रिकॉर्ड 720 लाख हेक्टेयर के साथ समाप्त हो गया है, जो पिछले 5 साल में सबसे अधिक है। ऐसे परिदृश्य में, हमें उम्मीद है कि ये लोन हमारे ग्राहकों को उनकी कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) की आवश्यकताओं को सुविधाजनक तरीके से पूरा करने में मदद करेंगे।

बिजली की दर 9 रुपए प्रति यूनिट तय

प्राकृतिक पेंट, वर्मी कम्पोस्ट के बाद अब गोबर से बन रही बिजली

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 मार्च के दिन विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 7 करोड़ 4 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। यह भुगतान 16 फरवरी से 28 फरवरी के दौरान लाभार्थियों से खरीदे गए गोबर एवं गौठान समितियों के लाभांश के लिए किया गया है। सरकार द्वारा अभी किए गए भुगतान में 16 फरवरी से 28 फरवरी तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय 2.13 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 4 करोड़ 25 लाख रुपए, गौठान समितियों को 1.65 करोड़ रुपए और महिला समूहों को 1.14 करोड़ रुपए की लाभांश राशि शामिल है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खुशी की बात है कि अब गोबर से अन्य उत्पादों के बनाने के अलावा बिजली बनाने का काम शुरू हो गया है। बस्तर के डोमरपाल में गोबर से बिजली बनाने के संयंत्र को ग्रिड से सिंक्रोनाईज किया जा चुका है। इससे बनने वाली बिजली की दर 9 रुपए प्रति यूनिट तय कर दी गई है। वही राज्य में गोबर से बिजली के अलावा प्राकृतिक पेंट, वर्मी कम्पोस्ट खाद जैसे कई अन्य उत्पाद भी तैयार किए जा रहे हैं।

गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को 15 मार्च के दिन भुगतान की गई राशि को मिलाकर अब तक 419 करोड़ 25 लाख का भुगतान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में 20 जुलाई 2020 से गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपए किलो में गोबर की खरीदी की जा रही है। राज्य में 28 फरवरी 2023 तक गौठानों में 107.75 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। गोबर विक्रेताओं से क्रय किए गए गोबर के एवज में 215 करोड़ 50 लाख का भुगतान किया जा चुका है। गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को अब तक 185 करोड़ 77 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

-बेंगलुरू में एग्री यूनिफेस्ट का केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया शुभारंभ

60 प्रतिशत युवा आबादी की ऊर्जा से भारत बनेगा विकसित देश: तोमर

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत एक विशाल लोकतंत्र है, जिसकी विशेषताओं में एक तो जनसंख्या और दूसरी हमारे युवाओं की 60 प्रतिशत आबादी है। ये दोनों ताकत मिलकर इतनी बड़ी है कि भारत किसी भी चुनौती का केवल मुकाबला ही नहीं कर सकता, बल्कि हम एक-दूसरे के पूरक बनकर चले तो इन चुनौतियों पर विजयी प्राप्त करने में भी पूरी तरह सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव से आगामी 25 वर्षों के समय को अमृत काल नाम दिया है, इसका ठीक से सदुपयोग हो और हमारे देश की युवा आबादी की ऊर्जा का भी सदुपयोग हो तो वर्ष 2047 तक हम अपने देश को विकसित भारत के रूप में अवश्य देख सकेंगे। केंद्रीय मंत्री तोमर ने यह बात बेंगलुरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आईसीएआर के सहयोग से आयोजित 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम एग्री यूनिफेस्ट में कही। इसमें 60 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/डीम्ड विश्वविद्यालयों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 2500 से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थी शामिल हुए हैं, जो 5 विषयों (संगीत, नृत्य, साहित्य, रंगमंच, ललित कला) के तहत 18 आयोजनों में अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। आईसीएआर द्वारा 1999-2000 के दौरान अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा महोत्सव की संकल्पना व शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य विभिन्न भारतीय संस्कृतियों को जोड़कर भारतीय कृषि को एकीकृत करना है, ताकि कृषि विश्वविद्यालयों के युवाओं की प्रतिभा निखर सकें और वे भारतीय सांस्कृतिक विविधता की सुंदरता को चित्रित करें। तोमर ने कहा कि समय की मांग है कि हम अपने जीवन के हरेक पल का पूरी तरह सदुपयोग करें।

मोटे अनाजों को प्रधानमंत्र मोदी ने एक नया अर्थ और आयाम प्रदान किया

इधर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में वैश्विक पोषक अनाज (श्री अन्न) सम्मेलन को संबोधित किया, जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्य अतिथि थे। नरेन्द्र सिंह तोमर ने अपने संबोधन में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष (आईवाईएम)-2023 वैश्विक उत्पादन बढ़ाने, दक्ष प्रसंस्करण और बारी-बारी से फसल के बेहतर उपयोग का अवसर प्रदान करेगा और मोटे अनाजों को खाद्य बास्केट के एक प्रमुख घटक के रूप बढ़ावा देगा। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष (आईवाईएम) घोषित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों के सहयोग से मोटे अनाजों के उत्पादन और उपभोग को बढ़ाने के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है। तोमर ने मोटे अनाजों को मानव जाति के लिए प्रकृति का उपहार बताया। उन्होंने कहा कि एशिया और अफ्रीका मोटे अनाज की फसलों के प्रमुख उत्पादन और उपभोग केंद्र हैं, विशेष रूप से भारत, नाइजर, सूडान और नाइजीरिया मोटे अनाजों के प्रमुख उत्पादक देश हैं और यह देखने की उनकी पूरी इच्छा है कि मोटे अनाजों को विश्व के हर खाने की थाली में स्थान मिले। मोटे अनाज एशिया और अफ्रीका में उगाई जाने वाली आरम्भिक फसलें थीं, जो बाद में विश्व भर में उन्नत सभ्यताओं के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत के रूप में विस्तारित हो गई।

एनएचबी ने सरल की सब्सिडी के लिए आवेदन और अनुमोदन की प्रक्रिया

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) देश में व्यावसायिक रूप में बागवानी और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए बैक-एंडेड पूंजी निवेश सब्सिडी योजनाएं संचालित करता है। इन योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लागत मानदण्डों के अनुसार विभिन्न घटकों के लिए 35 से 50 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाता है। योजनाओं के तहत दस्तावेजीकरण और स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कृषक समुदाय की मांग पर विचार करते हुए इस मामले की कृषि और किसान कल्याण मंत्री द्वारा समीक्षा की गई और विधिवत गठित एक समिति की सिफारिशों के आधार पर, योजना का स्वरूप, दस्तावेजीकरण और स्वीकृति को और आसान किया गया। योजना प्रारूप की मुख्य विशेषताएं: एनएचबी ने अब सैद्धांतिक अनुमोदन (आईपीए) और मंजूरी अनुदान (जीओसी) की दो चरणीय प्रणाली को समाप्त कर दिया है। अब आईपीए की आवश्यकता नहीं होगी और बैंक द्वारा सावधि ऋण की मंजूरी के बाद आवेदक सीधे एनएचबी को मंजूरी के लिए आवेदन करेगा। एनएचबी को ऑनलाइन दिए गए आवेदन की तारीख से 3 महीने के भीतर मंजूर हुए सावधि ऋण को वैध माना जाएगा। इच्छुक आवेदकों के लिए अब आईपीए प्रणाली को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) से बदल दिया गया है ताकि वे अपनी प्रस्तावित परियोजना के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से सावधि ऋण प्राप्त कर सकें। हालांकि आईपीए से अलग एलओसी अनिवार्य नहीं है और यह केवल उन आवेदकों को जारी किया जाएगा जो प्रस्तावित परियोजना के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से अपना सावधि ऋण प्राप्त करने के लिए एक सुविधा पत्र के रूप में इसे पाना चाहते हैं।

समृद्धि व समग्र विकास का माध्यम बन रहा है श्री अन्न: पीएम मोदी

भारत सरकार की अगुवाई में अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के उत्सव के अंतर्गत आयोजित दो दिवसीय वैश्विक मिलेट्स (श्री अन्न) सम्मेलन का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस उपलक्ष में प्रधानमंत्री ने डाक टिकट व सिक्के का अनावरण तथा श्री अन्न स्टार्टअप और श्री अन्न मानकों के संग्रह को डिजिटल रूप से लांच किया। साथ ही, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) से संबंधित भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) को बजट में की गई घोषणा के क्रम में उत्कृष्टता का केंद्र घोषित किया। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन व उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के साथ, प्रदर्शनी सह क्रेता-विक्रेता सम्मिलन मंडप का भी उद्घाटन किया। सम्मेलन में मोदी ने कहा कि श्री अन्न समृद्धि व समग्र विकास का माध्यम बन रहा है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। वहीं स्वागत भाषण में तोमर ने कहा कि देश के छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने श्री अन्न को प्रतिष्ठा प्रदान की है। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी प्रतिनिधियों को श्री अन्न के लिए भारत की ब्रांडिंग पहल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि श्री अन्न केवल भोजन या खेती तक ही सीमित नहीं हैं। भारतीय परंपरा से परिचित लोग किसी भी चीज के आगे श्री लगाने के महत्व को समझेंगे। श्री अन्न गांवों व गरीबों से जुड़ा हुआ है। श्री अन्न देश के छोटे किसानों के लिए समृद्धि का द्वार, करोड़ों देशवासियों के पोषण की आधारशिला व आदिवासी समुदाय का सम्मान है। श्री अन्न की फसल कम पानी में अधिक प्राप्त की जा सकती है, रसायनमुक्त खेती के लिए यह नींव है, वहीं जलवायु परिवर्तन से निपटने में मददगार है।

मसाला फसलों में तकनीकी हस्तांतरण कृषक प्रशिक्षण सह मेला

कम लागत में अधिक मुनाफे देती हैं मसाला फसलें: भारती

शिवपुरी। भारत सरकार के सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय केलिकट, केरल के मिशन फॉर इंडीग्रेटेड डेवलेपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर अंतर्गत मसाला फसलों में तकनीकी हस्तांतरण कृषक प्रशिक्षण सह मेला बुधवार 15 मार्च 2023 को राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केन्द्र पिपरसमां शिवपुरी पर आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रहलाद भारती उपाध्यक्ष मप्र पाठ्य पुस्तक निगम (राज्यमंत्री दर्जा) मप्र शासन भोपाल द्वारा किया गया एवं उन्होंने उपस्थित कृषकों, कृषक महिलाओं एवं छात्रों को संबोधित करते हुए शिवपुरी जिले के भौगोलिक एवं जलवायु दशा को फसलों में विविधता के अनुकूल बतलाया तथा जिले में मसाला फसलों-धनियां, अजवाइन, सोहा, कलोंजी, हल्दी, अदरक इत्यादि को भी फसल चक्र में समावेश कर वैज्ञानिक तकनीकियों से उत्पादन कर कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसलें साबित हो रही है साथ ही उन्होंने प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं कुछ क्षेत्र में किसानों को अपनाए जाने के लिए भी कहा जिससे भूमि, पर्यावरण एवं मनुष्य का स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव पड़े और इस हेतु देशज वंश के गौधन पालन को बढ़ावा दें। साथ ही उन्होंने शासन की उपयोगी योजनाओं से भी लाभान्वित होने एवं जुड़ने के लिए आह्वान किया।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)